लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का बड़ा दांव, पारित किया नया प्रस्ताव

विषय सूची (Table of Contents):

>> लोकसभा सीटों के भविष्य पर कांग्रेस का बड़ा दांव...
>> अगले 25 वर्षों तक 543 सीटें बरकरार रखने की मांग...
>> सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्य निर्णय...
>> संवैधानिक रोक और सीट बंटवारा...
>> तमिलनाडु के तर्ज पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित...
>> तमिलनाडु विधानसभा का हालिया प्रस्ताव...
>> राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता...
>> 2029 के चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने का आग्रह...
>> महिलाओं के लिए एक-तिहाई हिस्सेदारी...
>> मौजूदा सीटों के आधार पर आरक्षण...
>> परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल...
>> प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस का पलटवार...
>> मोदी संरक्षण बनाम महिला आरक्षण...
>> लोकसभा में विधेयक गिरने और राजनीतिक ड्रामेबाजी के आरोप...
>> बजट सत्र के दौरान आया था संकट...
>> भविष्य की सियासी राह...
>> निष्कर्ष...
>> जनता के सवाल (FAQs)...

लोकसभा सीटों के भविष्य पर कांग्रेस का बड़ा दांव

भारतीय राजनीति में एक बार फिर परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की एक महत्वपूर्ण बैठक इंदिरा भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्टी ने देश के चुनावी भविष्य और महिला प्रतिनिधित्व को लेकर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है, जिसने सत्ता पक्ष के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रशासनिक बदलावों और अन्य राष्ट्रीय खबरों पर भी लोगों की पैनी नजर बनी हुई है, जैसे कि हिमाचल में जॉब ट्रेनी नियम और EWS संशोधन (https: www.yojanasewa.com 2026 07 himachal-job-trainee-ews-rules-changed.html) से जुड़ी अपडेट्स।

अगले 25 वर्षों तक 543 सीटें बरकरार रखने की मांग

सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्य निर्णय

कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह मांग उठाई है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बिल्कुल वैसा ही बनाए रखा जाना चाहिए। पार्टी का तर्क है कि यदि अचानक सीटों की संख्या में फेरबदल किया जाता है, तो इससे विभिन्न राज्यों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है।

संवैधानिक रोक और सीट बंटवारा

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि राज्यों के बीच मौजूदा सीट बंटवारे पर लगी संवैधानिक रोक को आगामी 25 सालों तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस नीतिगत मांग से देश के कई राज्यों में राजनीतिक स्थिरता बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपलब्धियों की चर्चा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्राचीन भारत की महान खोजें (https: www.yojanasewa.com 2026 07 ancient-india-shocking-inventions.html) जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती हैं।

तमिलनाडु के तर्ज पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित

तमिलनाडु विधानसभा का हालिया प्रस्ताव

कांग्रेस पार्टी का यह कदम पूरी तरह से तमिलनाडु के राजनीतिक रुख से मेल खाता है। पिछले सप्ताह ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 पर स्थायी रूप से बनाए रखने की गुहार लगाई थी। उन्होंने 12 अगस्त 2026 को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का हवाला भी दिया था।

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता

तमिलनाडु के इस कदम के बाद कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में इसे शामिल करते हुए सीडब्ल्यूसी की बैठक में ठीक वैसा ही

प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि क्षेत्रीय दल और मुख्य विपक्षी दल मिलकर परिसीमन के मुद्दे पर एक मजबूत वैचारिक मंच तैयार कर रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कई अन्य नेता भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग (https: www.yojanasewa.com 2026 07 gautam-gambhir-resignation-demand-news.html) से जुड़ा मामला काफी सुर्खियों में रहा था।

2029 के चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने का आग्रह

महिलाओं के लिए एक-तिहाई हिस्सेदारी

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को सबसे ऊपर रखा गया है। पार्टी ने पुरजोर मांग की है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) आरक्षण को किसी भी देरी के बिना सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव से ही देश भर में लागू कर दिया जाना चाहिए।

मौजूदा सीटों के आधार पर आरक्षण

पार्टी नेताओं का मानना है कि इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही महिलाओं को उनका हक तुरंत दिया जा सकता है, जिससे संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी का मार्ग बिना किसी अड़चन के प्रशस्त हो सके।

परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवा

प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस का पलटवार

इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्षी दलों से परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण का समर्थन करने की अपील की गई थी। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे महज एक ड्रामा करार दिया है और सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

मोदी संरक्षण बनाम महिला आरक्षण

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण देना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करना है। पार्टी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि लाल किले से भाषणबाजी करने के बजाय सरकार को इच्छाशक्ति दिखाते हुए बिना देरी के 2029 के चुनाव में इस कानून को जमीन पर उतारना चाहिए।

लोकसभा में विधेयक गिरने और राजनीतिक ड्रामेबाजी के आरोप

बजट सत्र के दौरान आया था संकट

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा विवाद इस साल 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान घटी उस घटना से जुड़ा है, जब मोदी सरकार को झटका लगा था। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को उस समय आवश्यक बहुमत नहीं मिल सका था।

भविष्य की सियासी राह

सदन में विधेयक के गिरने के बाद से ही पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के इस नए प्रस्ताव और आक्रामक रुख ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनने वाला है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा तमिलनाडु के तर्ज पर पारित यह प्रस्ताव देश की चुनावी राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है। लोकसभा सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक 543 पर सीमित रखने और 2029 के चुनावों में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की मांग ने सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ा दिया है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस राजनीतिक और संवैधानिक चुनौती का सामना किस प्रकार करती है।

जनता के सवाल (FAQs)

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की यह महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली के इंदिरा भवन में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी।

कांग्रेस ने मांग की है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बिल्कुल वैसा ही बरकरार रखा जाना चाहिए और राज्यों के बीच सीट बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को किसी भी देरी या परिसीमन का इंतजार किए बिना सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए।

यह प्रस्ताव तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित उस प्रस्ताव की तर्ज पर है, जिसे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पहल पर प्रधानमंत्री को भेजा गया था।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील को ड्रामा करार दिया और आरोप लगाया कि उनका मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक हित साधना है।

संसद के बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी बहुमत नहीं मिल सका था, जिससे सरकार को झटका लगा था।

इस उच्चस्तरीय बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।